International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 11-09-2019; Accepted: 12-10-2019
www.educationjournal.in
Volume 4; Issue 6; November 2019; Page No. 54-56

मिथिलांचल में औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति

अजय कुमार
शोधार्थी, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगां, बिहार, भारत

सारांश
मिथिला में औद्योगिक विकास की संभावना तलाशनी है। मिथिला में उपजाऊ जमीन और बेशुमार जल संसाधन के साथ अपार पशुधन एवं मानव संसाधन उपलब्ध हैं। जाहिर सी बात है कि औद्योगिक विकास की कोई भी नीति इनकी उपेक्षा करके नहीं बनाई जा सकती। गंगा, कोशी गंडक, बागमती, महानंदा और इनकी सैकड़ों सहायक धाराओं से परिपोषित विशाल उपजाऊ जमीन औंर अथाह जल संसाधन मुंगेर, भागलपुर, बाँका, गोड्डा और दुमका जैसे खनिज एवं वन संसाधनों से भरपूर क्षेत्र नया इतिहास रच सकने में सक्षम है।

मूल शब्द: मिथिला, औद्योगिक, विकास, उपजाऊ

प्रस्तावना
वर्तमान मिथिला में यदि बिहार में अवस्थित जिलों को शामिल मानते हुए चलें तो यह तीन भागों में बँटा मिलता है। पहला पश्चिमी क्षेत्र जिसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय, शिवहर, दरभंगा और समस्तीपुर है। पूर्वी क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा जिला आता है। तीसरे क्षेत्र में गंगा के पार भागलपुर, मुंगेर और बाँका के अलावा वर्तमान झारखण्ड के कुछ जिले शामिल हैं। अब यदि इन तीनों क्षेत्रों में 60 के दशक के समय की औद्योगिक स्थिति को देखें तो पाएँगे कि पूरे मिथिला में कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछा हुआ था। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधबुनी, समस्तीपुर और पूर्णिया में चीनी मिलों की समृद्ध गतिविधि जारी थी जो क्षेत्र विशेष के कृषि उत्पादन को उद्योग से जोड़ने के साथ–साथ गांवों में छिपी हुई बेरोजगारी को श्रम संसाधन में परिवर्त्तित कर रही थी। पूर्णिया और कटिहार के जूट मिलों में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के उत्पाद निर्मित हो रहे थे और किसानों में जूट की खेती को बढ़ावा मिल रहा था। हायाघाट में पेपर मिल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। हैन्डलूम एवं रेशम का उद्योग भागलपुर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका था। इसके अतिरिक्त कम्बल निर्माण, चर्म उद्योग, चूड़ी उद्योग, बर्तन एवं बाँस की कारगरी के अतिरिक्त गुड़ बनाने की भी छोटी–छोटी इकाईयाँ पूरे मिथिला में फैली हुई थी। यही वह समय था जब बेगूसराय में थोड़े–थोड़े अंतराल पर पेट्रोलियम रिफाइनरी, खाद कारखाना और ताप विद्युत गृह की स्थापना हुई। इसके साथ ही मिथिला ने पहली बार गैर कृषि आधारित उद्योग के दर्शन किए साथ ही इन बड़े उद्योगों पर आधारित कई सहायक उद्योगों के खुलने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।
मगर आज उन तमाम गतिविधियों के परिणाम से हम सभी वाकिफ हैं कि लगभग सारे चीनी मिल बीमार हैं या बंद हो चुके हैं। मिथिला से गन्ने का उत्पादन समाप्तप्राय है। जूट मिलें दम तोड़ चुकी हैं। और जूट की फसल भी महज कुटीर उद्यागों को रस्सी बाँटने के लिए पहुँच रही है। अब इसका दोष सरकारी नीतियों पर मढ़ें या फिर नसीब को कोसें, तथ्य यही है कि पूरी मिथिला औद्योगिक मानचित्र से गायब है और ऐसा तब है जब सभी जिलों में जिला उद्योग विकास केन्द्र है और सभी जगह सरकार द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकार गठित है। ऊपर से ऋण देने और जमीन आवंटित करने की ढ़ेर सारी योजनाएँ भी हैं और पूँजी प्रदान करने वाले बैंक भी पर्याप्त है।

मिथिलांचल में औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति
मिथिला के विकास की नई रणनीति बनाई जानी आवश्यक है। इसके तहत दो बिन्दुओं पर समग्र क्षमता से कार्य करना जरूरी हैं, (1) कैसे मिथिला पूरे देश का अनाज भंडार बनकर उभरे और (2) कैसे मिथिला को जलीय उत्पाद एवं बगान उत्पाद का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाया जाए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग पूरी कर सके। अतः आवश्यक है कि हमारी योजना में प्रत्येक फसल के लिए अलग रणनीति बनाई जाय। भारत के अनाज भंडार के रूप में उभर कर यह क्षेत्र न केवल बढ़ती जनसंख्या को संतुलित और पोषक आहार करने में समर्थ होगा अपितु कृषि आधारित उद्योगों के लिए अतिरिक्त कच्चे माल की भी आपूर्ति करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि मिथिला के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से लैस किया जाय, ताकि वे गुणवत्ता वाले बीजों, रासायनिक खादों और अन्य दूसरे सूक्ष्म पोषकों का दक्ष एवं पर्याप्त इस्तेमाल कर सकें। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के साथ–साथ प्राकृतिक आपदाओं से निबटने में भी प्रशिक्षित करना जरूरी है।
इसी प्रकार– फलों में आम, लीची आदि एवं सब्जियों का भरपूर उत्पादन हमारे यहाँ होता है मगर इस पर आधारित उद्योग नगण्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तो एक भी नहीं। जरूरत है कि बागानों के उन्नयन का जिलावार निर्धारण कर उनके विकास की अलग रणनीति चिन्हित की जाय। पशुधन और डेयरी का विकास मिथिला के गाँवों के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई प्रदान करेगा। सुधा की सफलता अपने आप में एक कहानी है और कोई बड़ी बात नहीं कि इसे अन्य क्षेत्रों में नहीं अपनाया जा सकें। अपने विशाल और विविध जल भण्डार के कारण मिथिला जलीय उत्पादों का बड़ा स्त्रोत बन सकता है। इसकी नदियाँ, झील, मौन, चौर, पोखर और तालाबों को आज तक पूरी क्षमता से उपयोग में नहीं लाया जा सका है। यहाँ 4.55 लाख टन प्रतिवर्ष मछली की मांग है जबकि हमारा उत्पादन मात्र 2 लाख टन प्रतिवर्ष है। आवश्यक संरचना के इस्तेमाल से इसे 6 से 8 लाख टन प्रतिवर्ष आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा मखाना एक ऐसी जलीय उत्पाद साबित हो सकता है जिसपर एकाधिकार हो। जूट की माँग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ गई है। इस पर आधुनिक अनुसंधान ने एक नये टेक्सटाइल का विकास किया है और इसका प्रचलन आम हो रहा है। मिथिला में औद्योगिक विकास की संभावना तलाशनी है। मिथिला में उपजाऊ जमीन और बेशुमार जल संसाधन के साथ अपार पशुधन एवं मानव संसाधन उपलब्ध हैं। जाहिर सी बात है कि औद्योगिक विकास की कोई भी नीति इनकी उपेक्षा करके नहीं बनाई जा सकती। गंगा, कोशी गंडक, बागमती, महानंदा और इनकी सैकड़ों सहायक धाराओं से परिपोषित विशाल उपजाऊ जमीन औंर अथाह जल संसाधन मुंगेर, भागलपुर, बाँका, गोड्डा और दुमका जैसे खनिज एवं वन संसाधनों से भरपूर क्षेत्र नया इतिहास रच सकने में सक्षम है।
मिथिलांचल के विकास में उपलब्ध संसाधनों के भरपूर उपयोग से पूर्ण योगदान मिल सकता है। इस क्षेत्र की बहुत सी भूमि पानी में डूबी रहती है।

इस 'वेटलैन्ड' का समुचित उपयोग हम मखाना, सिंघाड़ा, खस की उपज एवं कैटफिश से कर सकते हैं। चूँकि विद्युत के मामले में मिथिला क्षेत्र आत्मनिर्भर नहीं है एवं इसके अभाव में क्षेत्र में विद्युत पर आधारित उद्योग सफल नहीं हो पा रहे हैं। अतएव बिजली के उत्पादन एवं उपलब्धता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मिथिलांचल एक कृषि प्रधान क्षेत्र है इसलिए उद्योग के क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फसल उचित प्रशोधन केन्द्रों के अभाव में बहुत नष्ट होती है विशेषकर सब्जियाँ। अतः किसानों के आमदनी में वृद्धि के लिए प्रशोधन केन्द्र एवं सुविधाओं का विकास अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में सिल्क के उत्पादन की संभावनाएँ बहुत हैं। अतः इस उद्योग को विकसित करना चाहिए। मिथिला के स्थानीय लघु–उद्योग भी प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं, उनके उत्पादन तकनीक एवं उत्पाद में नवीनीकरण होना चाहिए। इस क्षेत्र में चाय उद्योग के विकास के अवसर भी हैं। हस्तशिल्प के क्षेत्र में संगठित बाजार के अभाव में बहुत सारे हस्तशिल्पी या तो अन्य पेशे में जा रहे हैं या फिर उनके जीवन–स्तर में दिनानुदिन ह्रास हो रहा है। मिथिलांचल वर्तमान में बिहार राज्य का भाग है। बिहार राज्य गरीबी एवं बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। यहाँ की आर्थिक संरचना का प्रति लक्षण है कृषि पर निर्भर होना। यहाँ औद्योगिकीकरण की स्थिति अत्यन्त ही क्षीण है। सार्वजनिक उपक्रम बंद हो गए हैं। यहाँ की आर्थिक संरचना पर बाढ़ का अत्यन्त दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में, मिथिलांचल में औद्योगिक विकास की संभावनाओं और समस्याओं का आकलन वर्तमान अध्ययन की विषय–वस्तु है।

मिथिलांचल में औद्योगिक विकास कीं संभावनाएँ

मिथिलांचल बिहार राज्य का भाग है। बिहार की छवि देश के औद्योगिक मानचित्र पर बिल्कुल धूमिल है। बिहार में 1975–76 में रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या 3684 थी, 1988–89 में यह घटकर 3449 और 2011–12 में 3232 हो गई। 2013–14 में बिहार राज्य में निबंधित मध्यम, लघु और अतिलघु उद्यमों का वितरण तालिका 1.1 में दृष्टव्य है :–

तालिका 1.: 2013–14 में निबंधित मध्यम, लघु और अतिलघु उद्यमों का वितरण

प्रमंडल	इकाईयों की संख्या			
	अतिलघु	लघु	मध्यम	योग
पटना	759 (25.4)	64 (48.9)	4 (36.4)	827 (26.4)
मुंगेर	299 (10)	4 (3.1)	0 (0)	303 (9.7)
भागलपुर	102 (3.4)	0 (0)	0 (0)	102 (3.3)
पूर्णिया	243 (8.1)	5 (3.8)	0 (0)	248 (7.9)
मगध	364 (12.2)	14 (10.7)	0 0(	378 (12.1)
दरभंगा	197 (6.6)	9 (6.9)	0 (0)	206 (6.6)
कोशी	324 (10.8)	3 (2.3)	0 (0)	327 (10.4)
तिरहुत	527 (17.6)	5 (3.8)	2 (18.2)	534 (17.0)
सारण	160 (5.3)	4 (3.1)	0 (0)	164 (5.2)
बिआडा	16 (0.5)	23 (17.6)	5 (45.5)	44 (1.4)
योग	2991 (100.0)	131 (100.0)	11 (100.0)	3133 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक में दर्ज आंकड़े प्रतिशत को व्यक्त करता है।
स्त्रोतः उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट

पूर्व में देखा गया था कि बिहार में औद्योगिक इकाइयां सामान्यतः राष्ट्रीय औसत से छोटे आकार वाली है। बिहार के उद्योगों की यह ढ़ांचागत विशेषता प्रति कारखाना स्थिर पूँजी, निवल, मूल्यवर्धन और नियोजित लोगों की संख्या के जरिए भी अभिव्यक्त होती है जिनके आंकड़े तालिका 1.2 में प्रस्तुत है। देखा जा सकता है कि सम्पूर्ण भारत के स्तर पर प्रति कारखाना स्थिर पूंजी 11.10 करोड़ रूपये दर्ज हुई थी और बिहार में 2.63 करोड़ रूपये राष्ट्रीय आंकड़े का मुश्किल से एक चौथाई।[5] पुनः बिहार में प्रति कारखाना कामगारों की संख्या राष्ट्रीय आंकड़े का 64 प्रतिशत थी और प्रति कारखाना कर्मचारियों की संख्या सम्पूर्ण भारत के आंकड़े का 57 प्रतिशत। इसी प्रकार, प्रति कारखाना निवल मूल्यवर्धन सम्पूर्ण भारत के आंकड़े का 41 प्रतिशत था और प्रति कर्मचारी निवल मूल्यवर्धन सम्पूर्ण भारत के आंकड़े का 72 प्रतिशत।

तालिका 2.: बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात (2011–12)

विशेषताएँ	भारत		बिहार	
	समस्त	विनिर्माण	समस्त	विनिर्माण
प्रति कारखाना स्थिर पूंजी (लाख रू0)	1110	1046	263	259
प्रति कारखाना निवल मूल्यवर्धन (लाख रू0)	476	480	197	136
प्रति कारखाना कामगार (संख्या)	59	61	38	40
प्रति कारखाना कर्मचारी (संख्या)	76	79	44	
प्रति कर्मचारी शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रू0)	6.23	6.10	4.46	2.97

स्त्रोतः वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षणः2011–12

देश की तुलना में बिहार में मात्र 3.3 प्रतिशत उद्योग है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार के विनियोग का हिस्सा मात्र 5.4 प्रतिशत है जबकि यह अनुपात गुजरात में 11 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 9.1 प्रतिशत, तमिलनाडु में 11 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 21.2 प्रतिशत है। बिहार में 1932–33 में अधिकांश चीनी मिलें स्थापित किए गए। राज्य में कुल 29 चीनी कारखाने हैं जिनमें 18 चीनी मिलें सरकार के नियंत्रण में हैं एवं ये सभी बन्द हैं। निजी क्षेत्र में 11 चीनी कारखाने हैं जिनमें मात्र 4 कारखाने कार्यरत हैं। यहाँ के लिए चीनी उद्योग औद्योगिकरण की एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य कर सकता था किन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। मिथिलांचल का अशोक पेपर मिल चालू नहीं किया जा सका है। चर्म उद्योग, हस्करघा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, रेशम पालन उद्योग, ये सभी वित्तीय अभाव एवं तकनीकी पिछड़ेपन के शिकार है। स्वाभाविक है मिथिलांचल आज भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा है।

मिथिलांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेगी। प्राकृतिक खाद्य सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध है जो कृत्रिम आहार सामाग्री की तुलना में अधिक पौष्टिक एवं उपयोगी है। परिशोधित उत्पादन वृद्धि से देशी एवं विदेशी मांग की आपूर्ति की जा सकती है। मिथिलांचल में संभावनाएँ अपार है किन्तु गुणवत्ता, किस्मों में सुधार, विपणन, साख सुविधा आदि की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में कहा जा सकता है कि बहुआयामी उपायों के फलस्वरूप अनेक विदेशी एवं अप्रवासी भारतीय उद्योगपतियों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

मिथिला के औद्योगिक विकास का लक्ष्य केवल कृषि एवं डेयरी आधारित उद्योगों के विकास के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। यहाँ

- औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती
- फूलों की खेती
- मखाना की खेती
- मत्स्यपालन
- फलों एवं सब्जियों की खेती
- चीनी तथा कागज उद्योग
- मधुमक्खी पालन
- मिथिला पेंटिंग
- सांस्कृतिक –धार्मिक–पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देकर संभावनाओं का दोहन किया जा सकता है। इन पर आधारित बाजार और उद्योग स्वभाविक तौर पर विकसित होंगे। तब इनके लिए सड़कों और बिजली घरों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना आर्थिक बाध्यता बन जाएगी और जब मिथिला का सुदूरवर्ती गाँव भी मिथिला को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने के प्रयास से स्वयं को जोड़ सकेगा, तब यहाँ की परंपरागत कारीगरी, मिथिला पेंटिंग, लाह की चूड़ी, सीकी, मौनी और बाँस के उत्पादों को नया विस्तृत बाजार रूपी आकाश मिलेगा और नया जीवन दान भी। तभी सही अर्थों में मिथिलावासियों का जीवन स्तर उन्नत होग और मिथिला की अर्थव्यवस्था निम्न आय वर्ग से ऊपर उठकर आधुनिक एवं उच्च आय वर्ग में तब्दील होगी और यदि स्थानीय स्तर पर जीवनयापन की पद्धति सुधरती है तो आर्थिक विकास की दर

स्वाभाविक रूप से उन्नत हो जाती है। यही एक जीवंत समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की नई कहानी गढ़ता है।

सन्दर्भ सूची

1. पंसारी, संतोष कुमार (2011), मिथिला का आर्थिक विकासः एक सहप्रयास, मिथिलांचल के आर्थिक विकास की संभावनाओं पर दरभंगा में संगोष्ठी– अध्यक्षीय भाषण, 5 फरवरी
2. झा, प्रताप नारायण (2011), मिथिला में औद्योगिक विकास की संभावना, उद्यम, इण्डस्ट्रीयल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दरभंगा,
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना, फरवरी 2015, पृष्ठ 73
4. उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट
5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2011–12 के आंकड़े